CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

Decrease in water level in Mehsana District Gujarat

660. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:

SHRI SINH G. SOLANKI:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the Central Government are aware that the water level in the Mehsana district in Gujarat State is falling day-by-day and the epople of this are are facing acute hardship due to shortage of drinking water as well as the water for irrigation purpose;

(b) whether the Central Government have made any survey on the report of the State Government of Gujarat and made any efforts to improve the water level and provide drinking water by the natural sources;

(c) what is the progress in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes Sir. Longterm observations have shown a decline of 4—12 meters of shallow ground water and 10—50 meters of deeper ground water in Mehsana district of Gujrat. The fall in ground water level is due to over exploitation which has caused hardship to water supply systems.

(b) to (d) The Central Ground Water Board have established the feasibility of undertaking artificial recharge works to arrest the decline in ground water levels through a pilot project.

गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

661 **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने कुछ सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार नवीकरण तथा आधुनिकीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्य की सिंचाई सुविधाओं की गति तेज करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) (क) और (ख) उकई-काकरापुर सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण तथा मच्छू-1 सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण नामक दो स्कीमों क्रमशः नवम्बर, 1987 और फरवरी, 1991 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई हैं । उकई-काकरापुर स्कीम में 60 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर लगभग 50,000 हेक्टेयर को लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है । इस परियोजना को अगस्त, 1988 में परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया है । राज्य सरकार की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है मच्छू–1 सिंचाई स्कीम की अनुमानित लागत 6 करोड़ रुपए है तथा यह लगभग 26,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ प्रदान करेगी । राज्य सरकार को इस परियोजना की तकनीकी रिपोर्ट में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बतायी गयी कमियों को दूर करना है ।

(ग) निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में अपनायी गयी नीति में निर्माणाधीन परियोजनाओं,